आर.एन.आई. पंजीयन क्र. 39596/82 (डाक पंजीयन MP/IDC/1462/2016-2019)

साप्ताहिक

मालव अँचल

वर्ष 47 अंक 35 (प्रति रविवार) इंदौर, 19 मई से 25 मई 2024 पृष्ठ-8 मूल्य 3 रुपये

पांचवे चरण के साथ 429 सीटों पर मतदान पूरा, बाकी 2 चरणों में 114 सीटों पर वोटिंग होगी

रायबरेली में एक दर्जन ईवीएम खराब, मुंबई में उद्धव गुट के 3 कार्यकर्ता गिरफ्तार, बंगाल में भाजपा-टीएमसी समर्थक भिड़े

नई दिल्ली (एजेंसी)। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण का मतदान खत्म हो गया है। इस चरण में आठ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर 695 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे। इन सीटों पर 57.35 प्रतिशत वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 73 प्रतिशत और सबसे कम महाराष्ट्र में 48.88 प्रतिशत मतदान हुआ है। इसके अलावा ओडिशा विधानसभा के सेकेंड फेज की 35 सीटों पर 60.70 प्रतिशत, झारखंड की गांडेय विधानसभा सीट पर 68.26 प्रतिशत और लखनऊ ईस्ट सीट पर 52.25 प्रतिशत वोटिंग हुई है। जिन सीटों पर मतदान हुआ है, उनमें राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल जैसे केंद्रीय मंत्रियों के साथ राहुल गांधी की भी सीट शामिल हैं। 543 लोकसभा सीटों में पांचवें फेज तक 429 सीटों पर मतदान पूरा हो गया है। बाकी 2 चरणों में 114 सीटों पर वोटिंग होगी।

लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में 66.14 प्रतिशत, दूसरे चरण में 66.71 प्रतिशत और तीसरे चरण में 65.68 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई। 2019 के मुकाबले तीन चरणों में इस बार कम वोटिंग हुई थी। हालांकि, चौथे दौर में 96 सीटों पर 69.16 मतदान हुआ जबकि 2019 में इन सीटों पर

69.12 प्रतिशत वोटिंग हुई थी। उत्तर प्रदेश के महोबा में ड्यूटी के दौरान एक सीआरपीएफ जवान की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर और हुगली में भाजपा कैंडिडेट्स और टीएमसी समर्थकों के बीच झड़प हुई है। मुंबई में मतदान केंद्र के पास डमी ईवीएम रखने के आरोप में पुलिस ने शिवसेना के तीन कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। पांचवें चरण में बिहार में 52.35, जम्मू-कश्मीर में 54.21, झारखंड में 61.90, लद्दाख में 67.15, महाराष्ट्र में 48.66, ओडिशा में 60.55, उत्तर प्रदेश में 55.80 और पश्चिम बंगाल में 73 प्रतिशत मतदान हुआ। उधर, रायबरेली में करीब एक दर्जन ईवीएम खराब हो गईं। इस कारण मतदान काफी देर रूका रहा। शिकायत मिलने पर राहुल गांधी ने धांधली का आरोप लगाया।

अव्यवस्था के कारण कम हो रही वोटिंग

महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सोमवार को कहा कि मतदाता बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पर जा रहे हैं लेकिन असुविधा के कारण उन्हें वापस आना पड़ रहा है। उन्हें अंदर जाने में काफी समय लग रहा है। लोग वोट नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि भले ही समय लगे लेकिन मतदान केंद्रों पर जरूर जाएं और अपना वोट डालें। उन्होंने आगे कहा कि प्रशासन के कारण ही वोटिंग कम हुई है। जहां भी हमें बढ़त मिली है, वहां मशीनें ठीक से व्यवस्थित नहीं हैं। मशीनें बंद कर दी गई हैं। यह मोदी सरकार का नाटक है। हार का डर है। लोग उत्साहित हैं। उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। यह चुनाव आयोग का खेल है। जहां हमारा प्रतिशत ज्यादा होगा, वहीं मतदान प्रतिशत कम हो रहा है।

ममता बनर्जी के भाई ही नहीं डाल पाए वोट

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सबसे छोटे भाई बाबून बनर्जी सोमवार को मतदाता सूची में नाम नहीं होने के कारण अपना वोट नहीं डाल सके। बाबुन हावड़ा शहर के मतदाता हैं। जब वे मतदान केंद्र पर वोट डालने गए तो पता चला कि उनका नाम सूची में नहीं था। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता शांतनु सेन ने कहा कि चुनाव आयोग पूरे मामले को देख रहा है। केवल वही बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ। बता दें, ऐसी अफवाह थी कि बाबुन भाजपा में शामिल होने पर विचार कर रहे हैं। बाबुन बंगाल ओलंपिक एसोसिएशन, बंगाल हॉकी एसोसिएशन के अध्यक्ष के साथ-साथ बंगाल बॉक्सिंग एसोसिएशन के सचिव और टीएमसी के खेल विंग के प्रभारी भी हैं।

ईडी ने गृह मंत्रालय को आम आदमी पार्टी की विदेशी फंडिंग से जुड़ी रिपोर्ट सौंपी

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली के शराब नीति घोटाला मामले में फंसी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले से ही कोर्ट में चल रहे मामले के बीच अब ईडी ने आम आदमी पार्टी के विदेश फंड को लेकर बड़ा खुलासा किया है। जानकारी के मुताबित ईडी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को बताया है कि आप को 2014-2022 के दौरान 7.08 करोड़ रुपये का विदेशी फंड प्राप्त हुआ है। जांच एजेंसी ने पार्टी पर इस विदेश फंड को हासिल एफसीआरए, आरपीए और आईपीसी का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। इस फंड को हासिल करने के लिए विदेशी दानदाताओं की पहचान और राष्ट्रीयता के साथ-साथ कई अन्य तथ्यों को छिपाने जैसे आरोप ईडी ने अपनी रिपोर्ट में लगाए हैं। ईडी ने बताया कि आम आदमी पार्टी को संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, ओमान और अन्य देशों के कई दानदाताओं से धन प्राप्त हुआ। फंड ट्रांसफर करने के लिए विभिन्न दानदाताओं द्वारा एक ही पासपोर्ट नंबर, क्रेडिट कार्ड, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया है। ईडी ने अपनी जांच में आप और उसके नेताओं द्वारा विदेशी फंड जुटाने में अनियमितताओं के कई मामलों का जिक्र किया है। इसमें पार्टी विधायक दुर्गेश पाठक सहित कई नेताओं पर 2016 में कनाडा में फंड रेजिंग प्रोग्राम से जुटाए गए पैसे का व्यक्तिगत लाभ के लिए दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। साथ ही अनिकेत सक्सेना (आप ओवरसीज इंडिया के कॉर्डिनेटर), कुमार विश्वास (आप ओवरसीज इंडिया के तत्कालीन संयोजक, कपिल भारद्वाज (आप सदस्य) और पाठक सहित विभिन्न आप स्वयंसेवकों और पदाधिकारियों के बीच भेजे किए गए ई-मेल की सामग्री के जरिए आरोपों की पुष्टि की है।

3 नए क्रिमिनल कानूनों के खिलाफ याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट बोला- अपील करने में लापरवाही हुई, अगर बहस होती तो जुर्माना भी लगता

नई दिल्ली(एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता 2023 समेत तीन नए क्रिमिनल कानूनों की जांच और लागू होने के बाद सही ढंग से काम करने की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। याचिका में कहा गया था कि ये बिल संसद में बिना बहस के पास कर दिए गए। उस वक्त ज्यादातर विपक्षी सांसद सस्पेंड थे।

जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मिथल की वैकेशन बेंच ने कहा कि ये कानून अब तक लागू नहीं हुए हैं। अपील करने में भी लापरवाही हुई है। अगर इस पर ज्यादा बहस की जाती तो याचिका को जुर्माने के साथ खारिज किया जाता। बेंच के आदेश के बाद याचिका लगाने वाले एडवोकेट विशाल तिवारी ने कोर्ट से याचिका वापस लेने की परमिशन मांगी। इसके पहले सरकार ने बताया था कि भारतीय दंड संहिता में सुधारों के बाद ये तीनों कानून बने हैं। लोकसभा ने 21 दिसंबर 2023 को तीन बिलों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता बिल पास किए थे। 25 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन बिलों पर दस्तखत किए थे।

1 जुलाई से लागू होंगे 3 नए क्रिमिनल लॉ–तीन नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। सरकार ने 24 फरवरी 2024 को इससे जुड़ी अधिसूचना जारी की थी। यानी इंडियन पीनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएगा। नए कानून के लागू होने के बाद जो धाराएं अपराध की पहचान बन चुकी थीं, उनमें भी बदलाव होगा। जैसे हत्या के लिए लगाई जाने वाली आईपीएस की धारा 302 अब धारा 101 कहलाएगी। ठगी के लिए लगाई जाने वाली धारा 420 अब धारा 316 होगी। हत्या के प्रयास के लिए लगाई जाने वाली धारा 307 अब धारा 109 कहलाएगी। वहीं, दुष्कर्म के लिए लगाई जाने वाली धारा 376 अब धारा 63 होगी। हालांकि, हिट एंड रन केस का संबंधित प्रावधान तुरंत लागू नहीं होगा। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने जनवरी में कहा था कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) को लागू करने का फैसला अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से सलाह के बाद ही लिया जाएगा।

संपादकीय

भारत ईरान का बंदरगाह समझौता और तृतीय विश्व युद्ध की आशंका

ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हवाई दुर्घटना में हो गई है। उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। 17 घंटे के बाद हेलीकॉप्टर का मलमा मिला। राष्ट्रपति इब्राहिम, विदेश मंत्री हुसैन, पूर्वी अजरबेजान प्रांत के गवर्नर और अंगरक्षक हेलीकॉप्टर पर सवार थे। दुर्घटना के लगभग 20 घंटे के बाद ईरान सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर ईरान के राष्ट्रपति और उनके साथ जो लोग सवार थे, उनकी मौत की पुष्टि की है। ईरान के राष्ट्रपति अमेरिका में बने बेल 212 हेलीकॉप्टर में यात्रा कर रहे थे। हेलीकॉप्टर को खोजने में लगभग 17 घंटे का समय लगा। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घने कोहरे के कारण शायद आपातकालीन लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। ड्रोन फुटेज में जंगल में आग जलती हुई नजर आई। उसके बाद हेलीकॉप्टर मिला जो पूरी तरह से तबाह हो चुका था। यह दुर्घटना ऐसे समय पर हुई है जब ईरान के राष्ट्रपति रईसी और सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के नेतृत्व में पिछले महीने ही ईरान ने जबरदस्त ड्रोन और मिसाइल से इजराइल पर हमला किया था। कुछ दिन पहले भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह को लेकर एक समझौता हुआ था। इस समझौते के अनुसार ईरान के चाबहार बंदरगाह का स्वामित्व एवं संचालन का अनुबंध भारत की कंपनी के साथ किया गया था। ईरान के ऊपर अमेरिका ने कई वर्ष पहले से प्रतिबंध लगा रखे थे। इस समझौते के बाद भारत का खाडी के देशों और रूस के बीच समुद्री परिवहन निर्वाध रूप से होने लगता। इसका लाभ ईरान को भी मिलता। अमेरिका के लिए यह सबसे बड़ा धक्का था। इस समझौते के बाद ही आशंका व्यक्त की जा रही थी की विश्व स्तर पर अब कुछ ना कुछ बड़ा घटने जा रहा है। समझौते के ठीक एक सप्ताह के अंदर ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री का हवाई दुर्घटना में मौत हो जाना सामान्य दुर्घटना नहीं माना जा सकता है। इसके पीछे साजशि की आशंका बताई जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। नाटो देश और अमेरिका यूक्रेन का साथ दे रहा है। इसी बीच इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हो गया। अमेरिका, इजराइल को लड़ाई में हर संभव समर्थन दे रहा है। ईरान का जब इजराइल पर हमला हुआ, उसके बाद से स्थिति विस्फोटक होती जा रही थी। इजराइल से ईरान के ऊपर कोई बड़े हमले की आशंका बनी हुई थी। ईरान के राष्ट्रपति ने पिछले महीने पाकिस्तान का दौरा किया था। वहां से लौटने के बाद भारत के साथ बंदरगाह और रोड बनाने का समझौता ईरान ने किया। इस समझौते ने आग में घी डालने का काम किया। वैश्विक स्तर पर रूस और चीन, अमेरिका के मुकाबले में एक साथ खड़े हुए हैं। उत्तर कोरिया भी इसमें शामिल है। अमेरिका भारत और पाकिस्तान में से किसी एक को अपनी ओर खड़ा करना चाहता है। अमेरिका का समर्थन भारत वैसा नहीं कर रहा है, जैसा अमेरिका चाहता है। जिसके कारण अमेरिका, पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को मजबूत कर रहा है। आर्थिक रूप से पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। अमेरिका के लिए पाकिस्तान सॉफ्ट टारगेट है। इजराइल में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ उनकी कैबिनेट के मंत्रियों ने विद्रोह कर दिया है। गाजा के साथ युद्ध को लेकर कैबिनेट मंत्रियों ने नेतन्याहू को इस्तीफा देने की चेतावनी दे दी है। रूस और चीन मिलकर अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती दे रहे हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच 2 साल से ज्यादा समय से युद्ध चल रहा है। रूस के ऊपर जो अमेरिकी प्रतिबंध लगाए थे। इसका असर रूस और ईरान पर नहीं हुआ। रूस और चीन के मित्र देश एक नया वैश्विक समीकरण तैयार कर चुके हैं। उत्तर कोरिया आणविक हथियारों के साथ रूस और चीन के साथ सहयोग कर रहा है। वर्तमान स्थिति में भारत की विदेश नीति और कूटनीति दोनों ही बड़ी खराब स्थिति में पहुंच गए हैं। मोदी सरकार ने आर्थिक लाभ को देखते हुए, सामरिक स्थिति पर ध्यान नहीं दिया। रूस से सस्ते में कच्चा तेल लिया। अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भी ईरान के साथ व्यापार जारी रखा। चीन के साथ भारत के व्यापारिक रिश्ते चरम सीमा पर हैं।

झूठे वायदों एवं वादों से चुनाव को बचाना होगा

ललित गर्ग

लोकसभा चुनाव के चार चरण पूरे हो गये हैं, पांचवें चरण की ओर बढ़ते हुए चुनावी सरगर्मी बढ़ रही है। तमाम राजनीतिक दलों में वास्तविकता से दूर झूठे, तथ्य-आधारहीन, भ्रामक एवं बेबुनियाद वादे करने की आपसी होड़ बढ़ती जा रही है। राजनीतिक दल चार चरणों के बाद जिस तरह के जीत के तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं, वह हास्यास्पद एवं अविश्वसनीय है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव के 4 चरण पूरा होने के बाद विपक्षी 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस' यानी इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है और चार जून के बाद सरकार बनाएगा। इसी तरह ममता बनर्जी, अरविन्द केजरीवाल एवं अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की करारी हार की बात कही है। वर्ष 2019 के चुनाव के दौर भी इन नेताओं ने ऐसे ही बयान दिये थे, जो चुनाव परिणाम के बाद झूठे साबित हुए। इस तरह के अतिश्योक्तिपूर्ण, आधे-अधूरे, सत्यता से परे के बयानों से राजनीतिक दलों की विश्वसनीयता अपने निचले पायदान पर पहुंच चुकी है और तेज़ी से घट रही है। जिस प्रकार विभिन्न दलों के नेताओं की भाषा, बयान एवं लोकलुभावन वायदे निम्न स्तर पर पहुंच रहे है, उसे देखकर कहा जा सकता है कि हमारे लोकतंत्र का स्वास्थ्य कहीं-ना-कहीं खराब जरूर हो रहा है।

आम आदमी पार्टी (आप) के वादे और उनके काम के बीच फ़ासला लगातार बढ़ता रहा है, देश की भोली भाली जनता को आपका बेटा, आपकी बेटी कहकर सहानुभूति पाने की उसकी कुचेष्ठाओं का पर्दापाश पहले ही हो गया है। 'आप' ने अपने कामकाज के तरीक़े में पूरी पारदर्शिता का वादा किया था, लेकिन लोकसभा के लिए उम्मीदवारों के चयन में इसका ख्याल नहीं रखा गया है। हाल ही में पंजाब की चुनावी सभाओं में पार्टी नेता अरविन्द केजरीवाल ने बृजभूषण पर तो गंभीर आरोप लगाते हुए भाजपा को दागगार घोषित किया लेकिन वे अपने ही मुख्यमंत्री निवास पर राज्यसभा सांसद एवं पूर्व दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाती मालीमाल के साथ हुई मारपीट एवं अशिष्टता को भूल गये। निश्चित ही आप की कथनी और करनी में गहरा फासला है। इन्हीं केजरीवाल ने जनता को गुमराह करने एवं ठगने के लिये पिछले गुजरात के विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान एक सादे कागज पर अपने हस्ताक्षर करते हुए गुजरात में आप की सरकार बनने का दावा किया, जबकि उन चुनावों में आप के 4-5 सीटों पर जीत के अलावा सभी सीटों पर आप उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गयी थी। एक बार फिर इन लोकसभा चुनावों में वे ऐसा ही करते हुए झूठे दावे कर रहे हैं। इससे आप पार्टी की विश्वसनीयता एवं पारदर्शिता के दावों पर सवालिया निशान लग रहे हैं।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में दावा किया है कि उनकी पार्टी 2009 के आम चुनाव से बेहतर प्रदर्शन करेगी। यह दावा वास्तविकता से कोसों दूर है और राजनीतिक हलकों में उपहास का विषय बन गया है। जब कांग्रेस ने इन चुनावों में कोई लक्ष्य ही तय नहीं किया है तो कौन से लक्ष्य को पाने एवं जीत की बात कांग्रेस कर रही है? जैसे भाजपा ने 400 पार का लक्ष्य बनाया है, क्या कांग्रेस का ऐसा कोई लक्ष्य है? पार्टी के कार्यकर्ता बिना लक्ष्य के किसे अपना मिशन बनाये? कांग्रेस का एक दावा ये भी है कि वो लोकसभा में साफ सुथरी छवि वाले उम्मीदवारों को उतार रही है लेकिन वास्तविकता इसके उलट है। कई उम्मीदवारों को भ्रष्टाचार के उन आरोपों के बाद भी टिकट दिए गए हैं जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। हाल के दिनों में, प्रत्येक राजनीतिक दल के घोषणापत्र में वादों की लंबी चौड़ी फेहरिस्त सामने आयी है। जबकि अतीत में किए उनके काम बताते हैं कि सत्ता में आने के बाद वे अपने घोषणा पत्र के कुछ ही हिस्सों को लागू कर पाते हैं। जो सत्ता में नहीं आ पाते वो अपने घोषणापत्र को कूड़े के डब्बे में डाल देते हैं। विडम्बना तो यह भी है कि जिन दलों को चुनाव जीतने की आशा नहीं है, वे बेतूके वायदे एवं घोषणाएं करके आम मतदाता को भ्रमित करते हैं। शुरुआत से ही राजनीतिक दल वादे इसलिए करते हैं कि लोग उन्हें सत्ता की चाभी सौंपें। लेकिन चुनावी मौसम में राजनीतिक दल और राजनेता अपने अपने कामों के बारे में बढ़ चढ़कर दावे करते हैं और उन्हें भरोसा रहता है कि मासूम और भोली जनता उनके दावों पर यकीन कर लेगी, इसलिए वे लुभावने वादों की झड़ी लगा देते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने उत्तरप्रदेश की एक सभा में चार चरण पूरे होने के बाद भाजपा के 5 किलो मुफ्त अनाज की जगह 10 किलो मुफ्त अनाज की घोषणा कर है। बेवक्त पर की गयी यह घोषणा भी पार्टी की अपरिपक्वता को उजागर कर रही है। हालांकि ऐसे वादे हमेशा खाली जाते हैं या अधूरे रहते हैं। वादे करने का मतलब उसे पूरा करना ही नहीं होता। अतीत में, कांग्रेस की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ग़रीबी हटाओ के नारे के साथ 1971 का चुनाव ज़रूर जीता था। लेकिन लगातार दो बार सत्ता में आने के बाद भी देश से ग़रीबी नहीं हटी क्योंकि ज्यादातर सरकारी योजनाएं आम ग़रीबों तक पहुंची ही नहीं। अतीत गवाह है विगत दावों और वादों की हक़ीक़त का। हालांकि यह देखना बाक़ी है कि किसने सबक लिया और कौन अपने वादों और दावों के प्रति गंभीर रहेगा।

कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राजधानी लखनऊ में एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सपा प्रमुख ने दावा किया कि विपक्षी इंडिया' गठबंधन उत्तर प्रदेश में 79 लोकसभा सीटें जीतेगा, और सिर्फ एक सीट पर ही मुकाबला है। ऐसे अतिश्योक्तिपूर्ण बयान कभी सच होते हुए नहीं देखें गये हैं। निश्चित ही चुनाव परिणाम भविष्य के गर्भ में है एवं इसकी 4 जून को घोषणा सभी के लिये आश्चर्यकारी एवं चमत्कृत करने वाली होगी। देश का अगला प्रधानमंत्री चुनने के लिए चार चरणों की वोटिंग पूरी हो चुकी है। लोकसभा की कुल 543 सीटों में 380 सीटों के लिए वोट डाले चुके हैं। इन चार चरणों की वोटिंग के बाद हर राजनीतिक दल हवा का रुख भांपने को कोशिश कर रहा है लेकिन उनका यह आकलन सत्य से परे हो, बिलकुल ही आधारहीन हो, इसे लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिये अनुकूल नहीं माना जा सकता। यहां सत्ताधारी भाजपा से लेकर विपक्षी कांग्रेस सभी अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन चार चरणों में 270 सीटें जीतने का दावा करते हुए 400 का टार्गेट आसानी से पूरा करने की बात कही, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया है।

भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जो वायदें किये, उन्हें पूरा किया। 1990 के दशक और 21वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने के वादे के साथ सत्ता में आई एवं उसने मन्दिर बना दिया। भाजपा ने खुद को पार्टी विद डिफ़रेंस कहकर भी प्रचारित किया और जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को ख़त्म करने का वादा भी किया। उसने वह भी पूरा किया। पिछले 10 वर्षों में देश ने विकास की जो रफ्तार पकड़ी है, उसे देश एवं दुनिया खुली आंखों से देख रही है। फिर भी चुनाव का समय मतदाताओं के जागने एवं विवेक से अपना मतदान करने की अपेक्षा करता है। लोकतंत्र में मतदाताओं की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे चुनाव के अवसर पर राजनीतिक दलों की परख करें। झूठों एवं दुष्टों की एकजुटता ही जगत में कष्टों की वजह है एवं लोकतंत्र को कमजोर करने का बड़ा कारण है। जब तक ईमानदार एकजुट नहीं होंगे, तब तक जगत की कोई समस्या हल नहीं होगी। और ईमानदारों का एकजुट न होना दुष्टों एवं झूठों का असली बल है। कभी-कभी ऊंचा उठने, सत्ता पाने और भौतिक उपलब्धियों की महत्वाकांक्षा राष्ट्र को यह सोचने-समझने का मौका ही नहीं देती कि कुछ पाने के लिए उसने कितना खो दिया? और जब यह सोचने का मौका मिलता है तब पता चलता है कि वक्त बहुत आगे निकल गया और तब राष्ट्र अनिर्णय के ऊहापोह में दिग्भ्रमित हो जाता है। इस चुनाव को इस विम्बना से बचाना है।

531 कालोनियों के रेट जोन बदले संपत्तिकर और कचरा कर में हुई बढ़ोतरी

कांग्रेस विरोध में उतरी, कहा जनता को दे रहे हैं धोखा

इंदौर। *नगर निगम ने शहर की 531 कालोनियों के रेट जोन में बदलाव लागू कर दिया है। इन कालोनियों के संपत्तिकर और कचरा शुल्क में 10 प्रतिशत से लेकर 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है। इन कालोनियों के रहवासियों को बढ़ा हुआ शुल्क वर्ष-2024-25 से ही देना होगा। नई दरों को नगर पालिका के ई-पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया है। कांग्रेस इस शुल्क बढ़ोतरी के विरोध में उतर आई है।*

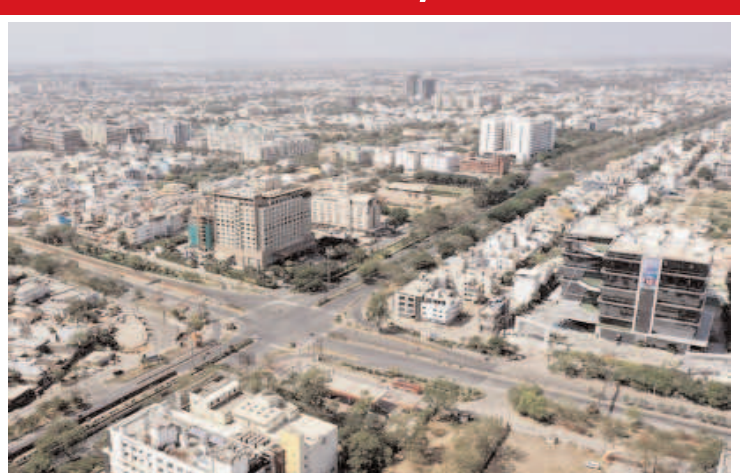

नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने इसे जनता के साथ धोखा बताते हुए कहा कि परिषद की बैठक में शोरगुल के बीच बगैर चर्चा बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूर कर दिया गया था। हमने उस वक्त आपत्ति दर्ज कराई थी जिसके बाद यह प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चल गया था। अब इसे लागू कर जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ाया जा रहा है।

नगर निगम का वित्तीय वर्ष-2023-24 का बजट 27 अप्रैल 2023 को पेश हुआ था। इसमें निगम ने कोई नया कर तो नहीं लगाया, लेकिन अपने खाली खजाने को भरने के लिए शहर की 531 कालोनियों के रेट जोन जरूर बदल दिए गए थे। वर्ष 2023 में विधानसभा चुनाव होने की वजह से इस प्रस्ताव को लागू करने के बजाय ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, जिसे अब लागू किया गया है।

निगम सीमा के 85 वार्ड की 531 कालोनियों में अधोसंरचनात्मक परिवर्तन, मूल्यांकन वृद्धि, भौगोलिक स्थिति और सुविधाओं के नाम पर संपत्ति मूल्य की गणना कर रेट जोन बदले गए हैं। इसके अलावा कचरा संग्रहण शुल्क भी बढ़ाया गया है। इसमें 20 रुपये से 30 रुपये तक कचरा शुल्क बढाया गया है।

इस बदलाव के बाद नगर निगम को इन 531 कालोनियों से प्रतिवर्ष 120 करोड़ रुपये ज्यादा मिलने की उम्मीद है। इधर बढ़ोतरी के विरोध में उतरी कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि वे इस संबंध में सोमवार को निगमायुक्त को ज्ञापन देंगे।

बदलाव में हैं कई विसंगतियां

रेट जोन में किए गए बदलाव में कई विसंगतियां भी हैं। बदलाव के बाद बड़ा सराफा, सांठा बाजार जैसे सघन और विशुद्ध व्यवसायिक क्षेत्र की संपत्ति का संपत्ति कर स्कीम 78 अरण्य नगर जैसी कालोनियों के समान हो गया है। शालीमार टाउनशिप, अनुराग नगर एक्टेंशन जैसी कालोनियों को इस बदलाव में जोन तीन से जोन एक में कर दिया गया है।

खजराना ब्रिज का काम 90 प्रतिशत पूरा

जून तक शुरू हो जाएगा ट्रैफिक

इंदौर। इंदौर में चार ब्रिजों का काम एक साथ शुरू हुआ है, लेकिन ट्रैफिक सबसे पहले खजराना ब्रिज पर शुरू हो जाएगा। इस ब्रिज की एक भुजा का काम 90 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है और इंदौर विकास प्राधिकरण जून के अंतिम सप्ताह तक उस पर ट्रैफिक शुरू करेगा। इस ब्रिज पर डामरीकरण भी शुरू हो चुका है। विद्युत साज-सज्जा, रंगाई-पुताई के अलावा ब्रिज का लोड टेस्ट किया जाना बाकी रह गई है। डामरीकरण का काम मंगलवार तक खत्म हो जाएगा। आईडीए के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आरपी अहिरवार ने बताया कि जून तक ब्रिज की एक भुजा पर ट्रैफिक शुरू हो जाएगा। इससे चौराहे पर यातायात का दबाव कम हो जाएगा। नंवबर तक दोनो भुजाएं ट्रैफिक के लिए खोल दी जाएगी। काम समयसीमा में पूरा हो, इसके लिए ठेकेदार को दो शिफ्टों में काम करने के लिए कहा गया है। इस चौराहे पर ग्रीन बेल्ट वाले हिस्से में दोनो भुजाएं बनाई गई है। बीच के हिस्से में मेट्रो ट्रेन चलेगी। खजराना चौराहे पर ट्रैफिक का दबाव सबसे ज्यादा रहता है। रिंग रोड पर यह चौथा ब्रिज बन रहा है। बंगाली, तीन ईमली, पिपलियाहाना चौराहे पर ब्रिज पहले बनाए जा चुके है।

लवकुश चौराहे का ब्रिज अक्टूबर तक होगा पूरा-लवकुश चौराहे पर डबलडेकर ब्रिज बन रहा है। एक ब्रिज का काम 75 प्रतिशत पूरा हो चुका है। प्राधिकरण ने अक्टूब तक ब्रिज का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा है। सुपर कॉरिडोर के अलावा इंदौर-सांवेर रोड की तरफ भी एक ब्रिज बन रहा है। दोनो ब्रिज की भूजाएं एक-दूसरे को क्रास करेगी। इस हिस्से में बन

विहिप की एमवाय अस्पताल से निशुल्क एम्बुलेंस शुरू

इंदौर। विश्व हिन्दू परिषद के केंद्रीय मंत्री अजय पारिख, एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय की मौजूदगी में एम वाय अस्पताल को एम्बुलेंस समर्पित कर जरूरतमंदों के लिए निशुल्क एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की। ज्ञात हो कि विश्व हिंदू परिषद इंदौर विभाग ने एम वाय अस्पताल के मरीजों हेतु विशेष एम्बुलेंस बनवाई है जो कि जरूरतमंद परिवार के मरीजों को मुफ्त मुहैया करवाई जाएगी। इस अवसर पर प्रांत अध्यक्ष मुकेश जैन, संगठन मंत्री खगेंद्र भार्गव, प्रांत सहमंत्री दिलीप जैन, सेवा प्रमुख गिरधारीलाल कुमावत, यज्ञेश राठी, विभाग संगठन मंत्री अभिषेक उदेनिया भी उपस्थित हुए।

इंदौर में 19 राउंड में पूरी होगी वोटों की गिनती चार बजे तक आ जाएंगे परिणाम

इंदौर। इंदौर में लोकसभा के चुनाव भाजपा के पक्ष में है, लेकिन भाजपा इंदौर से कितनी लीड़ लेगी और नोटा को कितने वोट मिलेंगे। लोगों की दिलचस्पी इसमें है। इंदौर में वोटों की गिनती चार जून को होगी। इंदौर में 62 प्रतिशत वोटिंग हुई है। जिनकी गिनती 19 राउंडों में पूरी होगी। इसके लिए नेहरु स्टेडियम में देपालपुर, सांवेर, दो, पांच और राऊ में 21-21टेबलों पर वोट गिने जाएंगे, जबकि राऊ,तीन और चार नंबर विधानसभा के लिए 14-14 टेबलें लगाई जाएगी। महू विधानसभा के वोटों की गिनती इंदौर में होगी, लेकिन उसकी जानकारी धार भेजी जाएगी। महू धार लोकसभा क्षेत्र में शामिल है। इंदौर में सुबह साढ़े सात बजे वोटों की गिनती शुरू होगी। पहले डाक मत पत्र गिने जाएंगे। उसके बाद अलग-अगल कक्षों में वोटों की गिनती होगी। नेहरु स्टेडियम में विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से स्ट्रांग रुम बनाए गए है। उन स्ट्रांग रुमों के बाहर सीआरपीएफ के जवान पहरा दे रहे है। 4 जून को मतगणना के रुझान सुबह 11 बजे से आना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले तीन नंबर विधानसभा क्षेत्र के वोटों की गिनती होगी। इस विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम वोटर है।

सबसे ज्यादा समय पांच नंबर विधानसभा क्षेत्र में लगेगा। भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे का कहना है कि इंदौर में 35 सालों से लोकसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार ने जीत दर्ज कराई है। इस बार जीत का अंतर दस लाख से ज्यादा होगा। कांग्रेस नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा का कहना है कि इंदौर की जनता नोटा में रिकार्ड बनाएगी। कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षय बम पर भाजपा ने दबाव बनाकर नाम वापस कराया है। भाजपा के इस फैसले से शहर का बड़ा तबका खुश नहीं है। देश में सबसे ज्यादा नोटा के वोटों इंदौर में गिरेंगे।

बूथ सर्वे ने भाजपा की बढ़ाई चिंता

चार लोकसभा सीटों पर गड़बड़ाया जीत का गणित

भोपाल। *मप्र की सभी 29 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए भाजपा ने विधानसभा चुनाव के साथ ही तैयारी शुरू कर दी थी। प्रदेश में चार चरणों में हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी ने पूरा दम लगा दिया। लेकिन मतदाताओं के मौन और कम मतदान ने पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में भाजपा ने बूथ सर्वे कराकर अपनी स्थिति का आकलन कराया है तो उसमें चौकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। बूथ सर्वे में रतलाम, राजगढ़, छिंदवाड़ा और मंडला सीट पर भाजपा की जीत का गणित गड़बड़ा रहा है। हालांकि इसके बार भी पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि भाजपा प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतेगी।*

गौरतलब है कि हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने के लक्ष्य के साथ भाजपा चुनावी मैदान में उतरी थी। पार्टी की रणनीति थी कि इससे भाजपा सभी 29 सीटें आसानी से जीत जाएगी। भाजपा के नेताओं का मानना है कि मोदी मैजिक के चलते इन सीटों पर उसे विजय मिल जाएगी। 2019 के चुनाव में भाजपा ने प्रदेश की 29 में से 28 सीटें जीत कर इतिहास रच दिया था। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में अपनी जीत पक्की करने के लिए कार्यकर्ताओं को बूथ जीता चुनाव जीता का मंत्र पहले ही दे दिया था। इसके लिए पार्टी बूथ पर पन्ना प्रमुख और अर्धपन्ना प्रमुख नियुक्त किए थे, जिन पर बूथ के

मतदाताओं को पार्टी के पक्ष में मतदान कराने की जवाबदारी थी।

कांग्रेसी दिग्गजों की सीट पर फोकस

भाजपा का फोकस प्रदेश की उन सीटों पर है जहां से कांग्रेस ने दिग्गज प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। इन सीटों में सबसे पहले नाम आता है छिंदवाड़ा सीट का जिसे भाजपा इस बार अपने खाते में डालने के लिए पूरे प्रयास कर चुकी है। साथ ही कांग्रेस के इस गढ़ को भेदकर वह इस सोच को बदलना चाहती है कि यह सीट कांग्रेस का अभेद किला है। यहां से भाजपा ने विवेक बंटी साहू को मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ से है। नकुलनाथ पिछली बार महज 36 हजार से चुनाव जीते थे। यही वजह है कि भाजपा की उम्मीदें इस बार उफान मार रही हैं। भाजपा के दिग्गजों ने इस बार यहां जोर लगाया है, इसके कारण कमलनाथ चुनाव तक छिंदवाड़ा से बाहर नहीं निकल सके। इसके अलावा भाजपा ने राजगढ़ सीट को अपनी विशेष महत्व वाली सूची में रखा है। यहां से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मैदान में हैं।

भाजपा जानती है कि दिग्विजय सिंह की राजगढ़ क्षेत्र में कैसी पकड़ है। वे पूर्व में दो बार यहां से सांसद रह चुके हैं। इसके बाद उनके भाई लक्ष्मण सिंह भी यहां का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। सिंह का मुकाबला भाजपा के दो बार के सांसद रोडमल नागर से है। वहीं आदिवासी अंचल की सीट मंडला में भी कांटे की टक्कर मानी जा रही है। यहां से भाजपा ने विधानसभा चुनाव हार चुके केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते पर एक बार फिर दांव लगाया है, तो कांग्रेस ने भी ओमकार सिंह मरकाम को मैदान में उतारा है। इसी प्रकार रतलाम-झाबुआ सीट पर भाजपा ने महिला प्रत्याशी अनिता नागर सिंह चौहान को टिकट दिया है, जहां उनका मुकाबला कांग्रेस के कद्दावर आदिवासी नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया से है। कांतिलाल यहां से चार बार सांसद रह चुके हैं। वे 2015 में हुए उपचुनाव में जीते थे पर 2019 में भाजपा के गुमान सिंह डामोर से हार गए थे।

भाजपा ने इस बार डामोर का टिकट काटकर वन मंत्री नागर सिंह चौहान की पत्नी अनीता को मैदान में उतारा है। नब्बे फीसदी आदिवासी मत वाली इस सीट पर भील और भिलाला समुदाय के बीच मतों का बंटवारा होता रहा है। कांतिलाल भील जाति से आते हैं तो अनीता भिलाला समाज से आती हैं। अब मतदान संपन्न होने के बाद पार्टियां अपनी-अपनी जीत का दावा कर रही हैं। किसको मतदाताओं का साथ मिला है यह 2 जून को साफ हो जाएगा।

रतलाम-राजगढ़, छिंदवाड़ा-मंडला ने बढ़ाई चिंता

मप्र में चार चरणों में हुए लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद भाजपा सभी 29 सीटों पर जीतने के दावे को पक्का करने के लिए बूथ स्तर पर सर्वे कराया है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि किस सीट पर पार्टी कितने अंतर से जीत रही है और किस सीट पर उसे विपक्षी दल से टक्कर मिल रही है। इस सर्वे में उसे चार सीटों रतलाम- झाबुआ, मंडला, छिंदवाड़ा और राजगढ़ में कांटे की टक्कर होने की रिपोर्ट मिली है। इससे उसकी चिंता बढ़ गई है। अब रिपोर्ट ली जा रही है कि वे बूथ पर कितने मतदाताओं से मतदान कराने में कितने सफल रहे। इसके अलावा बूथ स्तर पर एजेंट, बूथ प्रभारी एवं बूथ अध्यक्ष की टीम बनाई थी, जिसे त्रिदेव नाम दिया गया था। इनसे भी बूथ की पूरी जानकारी मांगी गई है। इस तरह भाजपा यह मालूम करना चाह रही है कि बूथ पर जो मतदान हुआ है उसमें उसके पक्ष में कितने वोट पड़े हैं। हालाकि मतदान की प्रक्रिया गोपनीय है फिर भी भाजपा इस तरह से मालूम करना चाह रही है कि बूथ पर जो मतदान हुआ है, उसमें उसे कितने वोट प्राप्त हो सकते हैं। इन त्रिदेव से बूथ पर जातिगत आधार पर मतदान के बारे में भी जानकारी ली जा रही है।

अल्प विराम-स्वयं से मुलाकात' कार्यक्रम आयोजित

भोपाल। राज्य आनंद संस्थान, आनंद विभाग द्वारा मंत्रालय वल्लभ भवन, सतपुड़ा एवं विंध्याचल में पदस्थ पुलिसकर्मियों के लिये दो दिवसीय 'अल्पविराम - स्वयं से मुलाकात' कार्यक्रम आयोजित किया गया। अल्पविराम शांत समय मे अंतरात्मा की आवाज को सुनने का एक अभ्यास है जो सकारात्मक सोच विकसित करने की प्रक्रिया को मजबूत बनाता है। अल्पविराम कार्यक्रम के माध्यम से जीवन में आंतरिक आनंद के महत्व पर चर्चा की गईद्य सेशन में विभिन्न टूल्स के माध्यम से जीवन का लेखा-जोखा, हमारे रिश्ते, चिंता का दायरा, प्रभाव का दायरा और विभिन्न रोचक गतिविधियों के माध्यम से जीवन में मानवीय मूल्यों के महत्व पर गहराई से सभी अधिकारियों कर्मचारियों के साथ चर्चा कर एवं अनुभव साझा किये। कार्यक्रम में मुख्य सुरक्षा अधिकारी/ सहायक पुलिस आयुक्त अविनाश शर्मा, पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी, राज्य आनंद विभाग के निदेशक प्रवीण गंगराड़े, कार्यक्रम समन्वयक मनु दीक्षित एवं मास्टर ट्रेनर राजेंद्र असाटी, प्रदीप महतो, सीमा अग्निहोत्री और मुकेश करुरा उपस्थित थे।

भोजशाला में एएसआइ सर्वे के दो महीने पूर

अब तक मिल चुके 1400 छोटे-बड़े अवशेष

भोपाल। भोजशाला में 60वें दिन सोमवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) की टीम ने गर्भगृह में मिट्टी हटाने का काम किया। टीम ने बाहरी परिसर में भी सर्वे किया, जबकि उत्तर व दक्षिण दिशा में खोदाई जारी रही। गर्भगृह में खोदाई के दौरान जो दीवारनुमा आकृति मिली थी, उसके पास 17 फीट तक खोदाई हो चुकी है।

इसी स्थान (भीतरी भाग) के उत्तर व दक्षिण भाग में चयनित ब्लाक में खोदाई हो रही है। सोमवार को यहां तीन-तीन फीट खोदाई की गई, लेकिन अभी दीवार का तल नहीं मिला है। हिंदू पक्ष के गोपाल शर्मा ने बताया कि भोजशाला में रखे स्तंभों की टीम ने फोटोग्राफी की और पिछले दिनों दक्षिण भाग में जहां खोदाई बंद हो गई थी, उसे भी आगे बढ़ाया गया। खोदाई में अब तक 1400 छोटे-बड़े अवशेष प्राप्त हो चुके हैं। इसके अलावा सिक्के और तलवार भी मिले हैं। बता दें कि हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के आदेश पर भोजशाला में 22 मार्च से एएसआइ सर्वे हो रहा है। सर्वे 27 जून तक चलेगा। सर्वे में अत्याधुनिक मशीनों के इस्तेमाल को लेकर हर बार यही कहा जा रहा है कि अगले सप्ताह वे धार आ जाएंगी, जबकि अब तक मशीनें नहीं आ पाई हैं। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में मशीनों से सर्वे करने के लिए भी कहा था।

भोजशाला में 60वें दिन सोमवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) की टीम ने गर्भगृह में मिट्टी हटाने का काम किया। टीम ने बाहरी परिसर में भी सर्वे किया, जबकि उत्तर व दक्षिण दिशा में खोदाई जारी रही। गर्भगृह में खोदाई के दौरान जो दीवारनुमा आकृति मिली थी, उसके पास 17 फीट तक खोदाई हो चुकी है। खोदाई में अब तक 1400 छोटे-बड़े अवशेष प्राप्त हो चुके हैं। इसके अलावा सिक्के और तलवार भी मिले हैं। बता दें कि हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के आदेश पर भोजशाला में 22 मार्च से एएसआइ सर्वे हो रहा है। सर्वे 27 जून तक चलेगा। सर्वे में अत्याधुनिक मशीनों के इस्तेमाल को लेकर हर बार यही कहा जा रहा है कि अगले सप्ताह वे धार आ जाएंगी, जबकि अब तक मशीनें नहीं आ पाई हैं।

मप्र की जेलों में जुलाई से लागू होगा नया कानून!

भोपाल। *गृह मंत्रालय ने 130 वर्ष पुराने जेल अधिनियम में बदलाव कर व्यापक माडल जेल अधिनियम-2023 तैयार कर लिया है। नए जेल अधिनियम में पुराने जेल अधिनियमों के प्रासंगिक प्रविधानों को भी शामिल किया गया है। यह राज्यों और उनके कानूनी क्षेत्र में मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में काम करने में सहायक होगा। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर मप्र के जेल विभाग ने मप्र सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदीगृह विधेयक-2024 बनाया है। इसके नियम तैयार कर लिए गए हैं।*

आचार संहिता हटने के बाद इस संबंध में प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इस विधेयक को जुलाई में होने वाले विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि प्रदेश में 11 केंद्रीय जेल हैं। वहीं 42 जिला जेल, 72 उप जेल, 7 ओपन जेल है। इन जेलों की बंदी क्षमता 30 हजार है। जबकि इनमें 48 हजार बंदी रखे गए हैं। सूत्रों का का कहना है कि प्रमुख सचिव जेल मनीष रस्तोगी, अपर सचिव ललित दाहिमा, डीजी जेल जीपी सिंह और जेल मुख्यालय के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में मॉडल जेल अधिनियम-2023 के ड्राफ्ट पर चर्चा कर मप्र सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदीगृह विधेयक-2024 के नियमों को अंतिम रूप देकर प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। जल्द ही यह प्रस्ताव विधि विभाग को भेजा जाएगा। वहां से यह प्रस्ताव मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली सीनियर सत्रेटीज की कमेटी में जाएगा। फिर इसे कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 130 साल बाद ब्रिटिश युग के 1894 के जेल अधिनियम में व्यापक स्तर पर संशोधन कर मॉडल जेल अधिनियम-2023 तैयार किया है। केंद्र ने सभी राज्य सरकारों को इसका ड्राफ्ट भेजा है। इस ड्राफ्ट में राज्य सरकारों से स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर जरूरी संशोधन करने को कहा गया है। इसी तारतम्य में मप्र का जेल विभाग मप्र सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदीगृह विधेयक-2024 ला रहा है। इसके नियम तैयार कर लिए गए हैं। जेल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि विधेयक में सबसे ज्यादा जोर जेलों में क्षमता से अधिक बंदी नहीं रखे जाने पर दिया गया है। जेलों में भीड़भाड़ के कारण रहने की स्थिति खराब होती है। इससे कई संचारी रोगों के संचरण का जोखिम बना रहता है। इससे निपटने के लिए मप्र में नए जेलों का निर्माण किया जा रहा है। नए जेल सागर, भिंड, दमोह, छतरपुर, रतलाम, मंदसौर व बैतूल में बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा जेलों में नए बैरकों का निर्माण किया जा रहा है।

आजादी से पहले का था जेल अधिनियम-1894

जेल अधिनियम-1894 आजादी से पहले के काल का अधिनियम था। इसका मुख्य उद्देश्य अपराधियों को हिरासत में रखना और जेल में अनुशासन व व्यवस्था बनाना था। मौजूदा अधिनियम में कैदियों के सुधार और पुनर्वास का कोई प्रविधान नहीं है। आज जेलों को प्रतिशोधात्मक निवारक के रूप में नहीं देखा जाता है अपितु इन्हें शोधनालय एवं सुधारात्मक संस्थानों के रूप में देखा जाता है, जहां कैदी बदलकर एवं पुनर्वासित होकर कानून का पालन करने वाले नागरिक की भांति समाज में लौटे।

मौजूदा कारागार अधिनियम में हैं कई खामियां

गृह मंत्रालय ने महसूस किया कि मौजूदा कारागार अधिनियम में कई खामियां हैं। मौजूदा अधिनियम में आज की आवश्यकताओं और जेल प्रबंधन की जरूरतों को पूरा करने का संशोधन करने की आवश्यकता थी। आधुनिक दिनों की आवश्यकता और सुधारात्मक विचारधारा के साथ गृह मंत्रालय ने जेल अधिनियम-1984 को संशोधित करने का काम पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो को सौंपा। मालूम हो कि ब्यूरो ने राज्य जेल अधिकारियों और सुधारात्मक विशेषज्ञों से बातचीत के बाद जेल प्रबंधन में प्रौद्योगिकी के उपयोग, अच्छे आचरण को प्रोत्साहित करने के लिए पैरोल, फरलो, कैदियों को छूट देने के लिए प्रविधान करना, महिलाओं व ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए विशेष प्रविधान करने आदि को शामिल कर ड्राफ्ट तैयार किया। गृह मंत्रालय ने जेल अधिनियम-1894, कैदी अधिनियम-1900 और कैदियों के स्थानांतरण अधिनियम-1950 की भी समीक्षा की है। इन अधिनियमों के प्रासंगिक प्रविधानों को माडल जेल अधिनियम-2023 में शामिल किया गया है।

जल्द फाइनल होगा फायर एक्ट का ड्राफ्ट

मप्र में 390 करोड़ से आधुनिक होंगी अग्निशमन सेवाएं

भोपाल। कई सालों से अटका हुआ फायर एक्ट जल्द ही मप्र में लागू करने की तैयारी चल रही है। नगरीय प्रशासन संचालनालय द्वारा लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले इस एक्ट का ड्राफ्ट फाइनल करके विभाग के प्रमुख सचिव को भेज दिया गया था। जल्द ड्राफ्ट को फाइनल करके आचार संहिता के बाद इसे कैबिनेट में लाने की तैयारी है। इसके बाद इसे विधानसभा के मानसून सत्र में भी लाया जा सकता है। कैबिनेट में लाने से पहले विधि विभाग के परीक्षण के लिए ड्राफ्ट को भेजा जाएगा। जानकारी के मुताबिक संचालनालय के अधिकारी जल्द ही प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई के सामने ड्राफ्ट का प्रेजेंटेशन देंगे। 2023 में सतपुड़ा भवन और इस साल वल्लभ भवन में हुए अग्निकांड के बाद सरकार फायर एक्ट लाने पर तेजी से काम कर रही है। दोनों ही घटनाओं के बाद बनी समितियों ने फायर एक्ट लाने की सिफारिश की है ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। एक्ट आने के बाद अग्निशमन सेवा का अलग स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। डायरेक्टोरेट फायर सर्विसेज बनेगा। नए फायर स्टेशन बनाए जाएंगे और हर नगरीय निकाय में एक फायर अफसर होगा।

सरकारी-निजी बिल्डिंगों के सेफ्टी ऑडिट की व्यवस्था बनेगी ताकि सुरक्षा की जिम्मेदारी तय की जा सके। फायर सर्विसेज को मजबूत करने के लिए पिछले साल सभी राज्यों ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा था। मप्र को प्रस्ताव पर लगभग 390 करोड़ का बजट मिलेगा। इस बजट से फायर एक्ट लागू करने और अग्निशमन सेवाओं को आधुनिक करने के लिए नए उपकरण खरीदने का मौका मिलेगा। इसके लिए प्रदेश को पहले फायर एक्ट फाइनल करके विधानसभा में पारित करना होगा।

2020 में बना था एक्ट का ड्राफ्ट-2019 में केंद्र ने राज्यों को फायर एक्ट बनाने के निर्देश जारी किए थे। एक्ट का ड्राफ्ट 2020 में बन गया था, लेकिन अभी तक कानून अस्तित्व में नहीं आ सका है। कुछ फेरबदल के बाद 2022 में नगरीय विकास एवं आवास संचालनालय ने एक्ट का ड्राफ्ट तैयार करके इसका नाम 'मप्र अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा अधिनियम- 2022' तय किया है। तब से ड्राफ्ट संचालनालय और विभाग के बीच फाइनल होने की प्रतीक्षा में है। एक्ट बनने के बाद निजी-सरकारी बहुमंजिला भवनों के सुरक्षा इंस्पेक्शन होंगे। तीन घंटे के नोटिस पर भी किसी भवन का फायर अफसर निरीक्षण कर सकेंगे। ड्राफ्ट में प्रॉपर्टी टैक्स के साथ बिल्डिंगों में फायर सेस लगाने का भी प्रस्ताव है। राज्य स्तर पर फायर-इमरजेंसी सर्विस बनाने का प्रावधान है।

15 दिन में बजट की रूपरेखा तैयार करेगी मोहन सरकार

भोपाल। मोहन सरकार का पूर्ण बजट जुलाई में होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। इसकी तैयारी वित्त विभाग ने प्रारंभ कर दी है। 15 दिन में वर्ष 2024-25 के बजट की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इसके लिए उप सचिव स्तरीय बैठकों का सिलसिला मंगलवार से प्रारंभ होगा। इसमें विभागीय प्रस्तावों पर विचार करके इन्हें मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव के समक्ष अंतिम निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इस बार बजट सवा तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का हो सकता है। सरकार एक लाख 48 हजार करोड़ रुपये का लेखानुदान प्रस्तुत कर चुकी है। इसमें जुलाई 2024 तक के लिए विभागों को राशि दी गई है। इसमें नई योजनाएं शामिल नहीं की गई थीं। अब पूर्ण बजट में नई योजनाओं के साथ-साथ उन योजनाओं को केंद्रीय योजनाओं में समाहित करने पर विचार होगा, जिनकी प्रकृति एक जैसी है। कुछ ऐसी योजनाएं भी चिह्नित की जाएंगी, जिनके लक्ष्य पूर्ण हो चुके हैं और बजट में शामिल हैं। सरकार की प्राथमिकता में रोजगार, औद्योगिक, अधोसंरचना विकास और हितग्राहीमूलक योजनाएं रहेंगी। इसके लिए विभागों को आवश्यकता के अनुसार राशि उपलब्ध कराई जाएगी। लाड़ली बहना, किसानों को गेहूं पर 125 रुपये प्रति क्विंटल बोनस, सिंहस्थ की तैयारी आदि के लिए संबंधित विभागों के लिए प्रविधान होंगे। नर्मदा जल के उपयोग के लिए सिंचाई परियोजना को प्राथमिकता में रखा जाएगा क्योंकि इस वर्ष दिसंबर में राज्य को आवंटित जल का उपयोग करना है। इसके लिए परियोजनाओं की स्वीकृति और निविदा प्रक्रिया प्रारंभ होना आवश्यक है। बजट के साथ-साथ वित्त मंत्री के भाषण की तैयारियां भी प्रारंभ कर दी गई है। इसके लिए 10 जून तक सभी विभागों से उपलब्धियां को विवरण मांगा गया है। इसमें भी पर्यावरण, जल संरक्षण, स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के क्षेत्र में किए गए कामों को प्रमुखता से रखा जाएगा। हितग्रहीमूलक योजनाओं के लाभार्थियों के बारे में अलग से जानकारी दी जाएगी।

भोपाल-इंदौर में 80 किमी की स्पीड में दौड़ेगी मेट्रो

साल के आखिरी में आम लोगों के लिए दौड़ सकती है मेट्रो

भोपाल। भोपाल और इंदौर में मेट्रो 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। भोपाल में इस स्पीड का ट्रायल में कामयाबी मिल चुकी है। हालांकि, ट्रैक पर मेट्रो ट्रेन 90 किमी की स्पीड से भी दौड़ाई जा सकती है। ताकि, ट्रैक और कोच के सिस्टम के सभी पैरामीटर पूरे हो सके। भोपाल में ट्रायल के बाद इंदौर में भी इसी स्पीड में ट्रेन जल्द ही दौड़ेगी। हर 2 मिनट में ट्रेन स्टेशन पर रुकेगी। भोपाल के सुभाष नगर से रानी कमलापति के बीच मेट्रो कोच को ट्रैक पर दौड़ाकर ट्रायल रन किया जा रहा है। अब तक की सबसे ज्यादा 80 किमी की स्पीड में मेट्रो दौड़ चुकी है। इसे बड़ी सफलता माना जा रहा है, क्योंकि जब भी मेट्रो का कमर्शियल रन शुरू होगा, तब यही रफ्तार रहेगी। मेट्रो कॉर्पोरेशन के अफसरों ने बताया, इतनी स्पीड में मेट्रो पहले कभी नहीं दौड़ाई गई। ट्रायल रन में यह 30 से 50 किमी की रफ्तार में ही दौड़ी है। एक बार 60 किमी की गति भी रह चुकी है, लेकिन अधिकतम गति 80 किलोमीटर ही है। अक्टूबर 2023 में ट्रायल रन होने के बाद कहा जा रहा था कि मई-जून में कमर्शियल रन भी हो जाएगा, लेकिन अभी ट्रैक और स्टेशनों पर काफी काम बाकी है। 6.22 किमी लंबा प्रायोरिटी कॉरिडोर है। इसमें से सुभाषनगर से आरकेएमपी तक 5 स्टेशन भी शामिल हैं। इसके बाद डीएमआर ऑफिस, अलकापुरी और एम्स के बीच ट्रैक पर काफी काम बाकी है।

धक-धक गर्ल को स्कूल में मिली थी पहली फिल्म

माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 को एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। माधुरी को बचपन से ही डांस में दिलचस्पी थी। ऐसे में महज 3 साल की उम्र से उन्होंने ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। माधुरी ने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि उन्हें पहली फिल्म कैसे मिली। आज उनके जन्मदिन के खास मौके पर हम आपको उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ खास बातें बताने वाले हैं।

माधुरी की पहली फिल्म

माधुरी ने कहा था कि- वह जब उनकी 12वीं की छुट्टियां हुई तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ नया किया जाएं। उस दौरान राजश्री प्रोडक्शन अपनी फिल्म अबोध के लिए नया चेहरा तलाश रहे थे। राजश्री से जुड़े एक शख्स की बेटी की दोस्त माधुरी की बहन थी। ऐसे में राजश्री को जब उनके बारे में पता चला तो वह खुद फिल्म अबोध का ऑफर लेकर माधुरी के घर पहुंचे।

इन फिल्मों से मिली थी लोकप्रियता

हालांकि इसके बाद माधुरी दीक्षितने हार नहीं मना और लगातार कई फिल्मों में काम किया। हालांकि वह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। जिसके बाद सुभाष घई ने अभिनेत्री को एक और मौका दिया। उनकी सबसे सफल फिल्मों की बात करें तो वह फिल्म तेजाब, राम लखन, त्रिदेव, किशन कन्हैया, और देवदास शामिल हैं।

रिया चक्रवर्ती से लेकर दीपिका तक

ड्रग्स के जाल में फंस चुकी हैं बॉलीवुड की ये एक्ट्रेसेस

बॉलीवुड में कई एक्ट्रेसेस हैं जो अपनी रील लाइफ के साथ रियल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रही। ये चर्चा उनके बॉयफ्रेंड और अफेयर को लेकर थी लेकिन इस बीच इनकी चर्चा तब आग की तरह फैली जब बॉलीवुड की इन एक्ट्रेसेस का नाम ड्रग्स से जुड़े केस में आया। वैं से बॉलीवुड और ड्रग्स का रिश्ता काफी समय पहले थे लेकिन एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कई एक्ट्रेसेस ड्रग्स के जाल में फंसती हुई नजर आई। आज हम आपको उन्ही एक्ट्रेसेस के बारे में बताने जा रहे हैं जो ड्रग्स के केस में फंस चुकी हैं।

रिया चक्रवर्ती

एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती का नाम ड्रग्स केस में तब शामिल हुआ जब एक्टर सुशांत सिंह राजपूत अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे। वहीं इस समय रिया चक्रवर्ती उनके साथ रिलेशनशिप में थी। वहीं इस मामले की जांच हुई और मामला ड्रग्स का पाया गया। वहीं इस ममाले में रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया साथ ही उन्हें कई समय तक जेल में भी रहना पड़ा।

दीपिका पादुकोण

एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण भी ड्रग्स के जाल में फंस चुकी हैं। सुशांत सिंह राजपूत मौत से जुड़े मामले में जब करवाई की जा रही थी तब एक्ट्रेस दीपिका नाम भी चैट के जरिए सामने आया। एक्ट्रेस को लेकर कहा गया कि एक्ट्रेस ने ड्रग्स की की डिमांड की थी और तब न हृष्टक ने एक्ट्रेस को पूछताछ के लिए बुलाया था।

श्रद्धा कपूर

सुशांत सिंह राजपूत केस में करवाई के दौरान श्रद्धा कपूर का नाम भी सामने आया था। एक्ट्रेस को लेकर खुलासा हुआ था कि एक्ट्रेस ने सीबीडी ऑयल मांग रही हैं। ये सीबीडी ऑयल ड्रग होता हैं। वहीं एक्सट्रेस का नाम सामने आने के बाद श्रद्धा कपूर को पूछताछ के लिए बुलाया था और इस दौरान वो खूब चर्चा में रही। आपको बता दें कि ड्रग्स केस में भारती सिंह उनके पति, सारा अली खान साथ ही बॉलीवुड के कई सारे एक्ट्रेसेस हैं जो ड्रग्स के जाल में फंस चुकी हैं।

अक्षय कुमार संग बड़े पर्दे पर नजर आएंगी आलिया भट्ट

आखिरी बार 'बड़े मियां छोटे मियां' में नजर आने के बाद अक्षय कुमार और 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' एक्ट्रेस आलिया भट्ट इन दिनों अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इसी बीच एक खबर सामने आ रही हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि दोनों की जोड़ी एक साथ बड़े पर्दे पर नजर आ सकती है।

जब लारा दत्ता को हुआ शादीशुदा शख्स से प्यार, तुड़वा दी 7 साल की शादी

लारा दत्ता बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक मशहूर अभिनेत्री है और आपको बता दें कि उन्होंने काफी बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। हालांकि अब वह फिल्मी दुनिया से दूर है और अपने परिवार के साथ वक्त बिताती हैं। लेकिन एक वक्त था जब उन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया और बी टाउन की खूबसूरत अभिनेत्री बन गई थी। हालांकि आपको बता दें कि लारा दत्ता अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में रही। उन्होंने टेनिस प्लेयर महेश भूपति के साथ में शादी रचाई। उनकी शादी को 13 साल पूरे हो चुके हैं। हालांकि दोनों की जोड़ी भी बहुत ही लाजवाब है। लव स्टोरी उससे भी ज्यादा दिलचस्प है।

खबरों के अनुसार महेश ने पहली बार एक्ट्रेस को साल 2000 में मिस यूनिवर्स बनने के बाद देखा। तब तक वह एक मशहूर टेनिस प्लेयर बन चुके थे और पहली बार एक्ट्रेस को देखने के बाद ही उन्हें पसंद करने लग गए थे।लेकिन लारा दत्ता और महेश भूपति की पहली मुलाकात एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी की एक बिजनेस मीटिंग के वक्त हुई थी। यहां पर लारा दत्ता ने महेश की कंपनी को अपने काम का मैनेजमेंट देखने के लिए कह दिया था। मीटिंग के बाद दोनों की मुलाकात बड़ी और दोनों की नजदीकियां भी बढ़ने लगी।जानकारी के लिए आपको बता दें कि महेश भूपति पहले से ही शादीशुदा थे। उन्होंने इससे पहले मॉडल श्वेता जयशंकर के साथ में शादी की थी। हालांकि आपको बता दें कि किसी कारणों के चलते 7 साल में दोनों की शादी टूट गई थी। बाद में महेश भूपति और लारा दत्ता ने 16 फरवरी 2011 को शादी कर ली।

जीवन के अनुभवों से सीखने, बदलाव के लिए तैयार रहने और विचारों के मतभेद का सम्मान करने का लचीलापन आपको मैच्योर लोगों की जमात का हिस्सा बना सकता है। 20, 40 या 70 साल, आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सी उम्र में एक व्यक्ति मैच्योर या परिपक्व कहलाता है? असल में परिपक्वता का उम्र से कोई लेना-देना नहीं होता। यह पूरी तरह से आप पर निर्भर है कि आप कब मैच्योर होना चाहते हैं।

खुद को बनाना है मैच्योर तो...

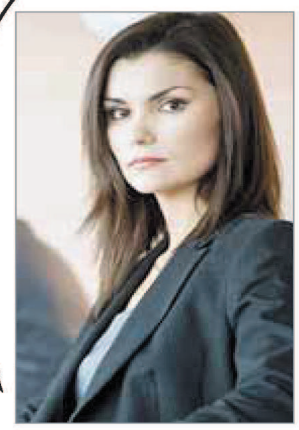

न्यूज चैनल्स पर सार्थक बहस की बजाय वक्ताओं का एक-दूसरे पर चिल्लाना, सड़क पर वाहन चालकों का हिंसक रवैय्या और सार्वजनिक जगहों पर शर्मसार करने वाली घटनाओं से हमें रोजाना रूबरू होना पड़ता है। ऐसी स्थिति में हमारे मन में यही प्रश्न उठता है कि लोग इतनी अपरिपक्व सोच क्यों रखते हैं? दरअसल परिपक्वता और आत्मबोध हासिल करने की जिम्मेदारी हमारी अपनी है।

दूसरों को दोष न दें

अपनी समस्याओं का दोष किसी और को देना बचपना होगा। खुद को किसी मुश्किल परिस्थिति में धकेलने की जिम्मेदारी अपने पैरेंट्स, टीचर, दोस्त या किसी और पर थोप कर आप उससे बच नहीं सकते। अपनी गलती को स्वीकार करना, उनसे सीख लेना और विफलता से न डरना मैच्योर होने की पहचान है।

सहनशील बनें

परिपक्व होने का मतलब है दुनिया को उसके असल रूप में स्वीकारना और विरोधाभासों को सहन करना। जब आप मानसिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं तो दुनिया और खुद के प्रति आपकी समझ विकसित हो जाती है। सहनशीलता आपको विपरीत परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की शक्ति देती है।

फीडबैक लेते रहें

मैच्योर लोग आगे बढ़ते हुए आलोचना को भी महत्व देते हैं चाहे वह नकारात्मक हो या सकारात्मक, इसलिए इससे भागने की बजाय इसे सुधार का जरिया बनाएं और इसके लिए धन्यवाद भी दें। यही नहीं, आलोचना होने पर आगे बढ़ कर सलाह मांगें और यह पूछें कि बेहतर बनने के लिए क्या करना होगा।

खुद पर हंसना सीखें

हंसने की वजह तलाश लेना बुरी से बुरी स्थिति में भी दिमाग को शांत रखने का सबसे अच्छा तरीका है। जब आप साधारण चीजों में भी हास्य देख पाते हैं तो परेशानियों को पीछे छोड़ आगे बढ़ने में ज्यादा सक्षम होते हैं। जो हो चुका, उसके दुख में डूबे रहने की बजाय हंसी में भुला दें और फिर से कोशिश करें।

खुद पर हो फोकस

दूसरे लोग क्या कहते हैं, करते हैं और सोचते हैं, इससे आपका कोई ताल्लुक न होने पर भी अगर आप विचलित हो जाते हैं तो यह समझदारी नहीं है। अगर आप मैच्योर होना चाहते हैं तो दूसरों की बजाय जो आपके पास है, उस पर फोकस करें। वही करें, जो आपको अपने लिए और अपनों के लिए करना है। आलोचना और रचनात्मक नहीं हैं तो उस पर ध्यान न दें। नफरत या तुलना को भूल जाएं। बस खुद पर फोकस करें।

डटे रहें

मांग पूरी न होने पर बच्चे पैर पटक कर रो देते हैं। उन्हें लगता है कि गुस्सा दिखाने से उनकी बात मान ली जाएगी, पूरी नहीं हो शायद कुछ हद तक। वहीं वयस्क होने के नाते हमें पता है कि प्रगति के रास्ते में अस्वीकृति मिलने या समस्याएं खड़ी होने पर हार नहीं माननी चाहिए। भावनाओं पर काबू रखें और जो महत्वपूर्ण है उस पर नजर बनाएं रखें। तुरंत आवेग में न आएं, दूर की सोचें।

ज्यादा न सोचें

किसी भी परिस्थिति का बार-बार अवलोकन करना आपको आसानी से विचलित कर सकता है। ईमेल, मैसेज, टैक्स्ट और ट्वीट की गहराई में न डूबें। समस्याओं को सुलझाने के लिए अलग-अलग तरीके आजमाने की बजाय क्रिएटिव और गहन सोच का इस्तेमाल करना समझदारी होगी।

लक्ष्य पर नजर

मैच्योर लोगों की कुछ उम्मीदें, सपने और महत्वाकांक्षाएं होती हैं, जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। वहीं अपरिपक्व लोग दिल और दिमागी तौर पर आगे बढ़े बिना चीजें हासिल करना चाहते हैं।

परिपक्व लोग खुद की बेहतरी पर समय का निवेश करते हुए समाज को बेहतर बनाने में भी अपना योगदान देते हैं, क्योंकि वे अपनी जिम्मेदारी समझते हैं।

आप भी पूरा कर सकते हैं गार्डनिंग का शौक

गार्डनिंग बहुत से लोगों का शौक होता है। मैट्रो शहरों में रहकर इस शौक को पूरा करना थोड़ा मुश्किल होता है पर असंभव नहीं, क्योंकि मैट्रो शहरों में फ्लैट सिस्टम के होते आप घर के बाहर लान तो बना ही नहीं सकते। बस ग्राउंड फ्लोर वाले लोग इस शौक को आसानी से बरकरार रख सकते हैं, लेकिन घबराइये नहीं। फ्लैट्स में रहकर गार्डनिंग लान के रूप में तो नहीं हो सकती पर गमलों में पौधे लगा कर शौक पूरा किया जा सकता है। गार्डनिंग के शौक को पूरा करने के लिए पहले कुछ जानकारी एकत्रित कर लें तो थोड़े से पौधों का ध्यान अच्छी तरह रख सकते हैं। मसलन- कौन सी मिट्टी, कितना पानी, कौन सी खाद और किस मौसम में कौन सा पौधा उग सकता है, इस बारे में जानकारी एकत्रित कर लें। फिर इस बात पर ध्यान दें कि गमले आप बालकनी में कहां रखेंगे और वहां कितनी धूप और हवा आती है।

गार्डनिंग के लिए उचित औजार भी खरीद लें ताकि उनकी कटिंग, रोपाई आदि आसानी से कर सकें। इसके लिए खुरपा, फव्वारा और कटर अवश्य अपने पास रखें। एक छोटा पानी स्प्रे करने वाला पॉट भी रखें ताकि छोटे पत्ते वाले पौधों को साफ किया जा सके। अपने लिए वाटरप्रूफ दस्ताने भी अवश्य रख लें। गमलों को बाहर से पेंट कर बालकनी में रखें। ऊंचे पौधों वाले गमले पीछे और छोटे पौधे वाले गमले आगे रखें ताकि छोटे पौधे वाले गमले बड़े पौधों के पीछे छिपकर अपनी सुंदरता कम न कर दें। नया पौधा लगाते समय उस गमले की मिट्टी बाहर निकाल कर उसमें खाद मिलाकर गमले में भरें ताकि गमले में नया पौधा आसानी से अपनी जड़ पकड़ सकें। बीच-बीच में सीजनल फूल भी लगाएं ताकि फूलों की सुंदरता का आनंद उठाया जा सके। बस ध्यान दें कि सीजन खत्म होते ही उसमें दूसरे पौधे लगवा लें।

कुछ ऐसे पौधे गमलों में लगायें जो सारा साल हरे-भरे रहें ताकि आपकी बगिया हरी भरी रहे। जो भी पौधा लगाने जा रहे हैं, उसकी जानकारी लेबल से पढ़ लें। कितनी धूप और कितनी छांव की आवश्यकता है, इस बारे में भी निर्देश पढ़ लें। गमले पौधों की लंबाई अनुसार खरीदे जाएं और धूप व छाया का ध्यान रखा जाए।

कलेक्टर फिर एक्शन मोड में, दिए निर्देश

फायर सेफ्टी नहीं होने पर हाईराइज बिल्डिंग करेंगे सील

इंदौर। ऊंची बिल्डिंगों में फायर सेफ्टी की जरूरत को लेकर कलेक्टर आशीष सिंह एक बार फिर एक्शन मोड में हैं। कलेक्टर सिंह ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 12 मीटर से ऊंची बिल्डिंग में फायर सेफ्टी नॉर्म्स जरूरी हैं। यदि ऐसी बिल्डिंगों में फायर सेफ्टी नहीं पाई जाती तो उन्हें सील करने की कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर सिंह ने स्पष्ट किया है की बिल्डिंग चाहे रहवासी हो या कमर्शियल या सेमी कमर्शियल फायर सेफ्टी अत्यंत जरूरी है। लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। लोकसभा चुनाव की वोटिंग हो चुकी है। अधिकारी कर्मचारी चुनाव ड्यूटी से फ्री हो चुके हैं। इसलिए एक बार फिर फायर सेफ्टी को लेकर अभियान चलाया जाएगा।

कलेक्टर आशीष सिंह ने जब से इंदौर में कलेक्टर का चार्ज संभाला है तभी से वह रहवासियों की सुरक्षा को लेकर अत्यंत गंभीर हैं। इसके लिए उन्होंने समय-समय पर 12 मीटर से ऊंची बिल्डिंग और कम ऊंचाई की बिल्डिंगों के लिए भी फायर सेफ्टी नॉर्म्स पूरे किए जाने की जरूरत पर जोर दिया है। कुछ समय पूर्व इसके लिए एक अभियान भी चलाया गया था और कुछ बिल्डिंगों में जहां फायर सेफ्टी नहीं पाई गई थी, उन्हें सील भी किया गया था। हालांकि बिल्डिंग

मालिकों द्वारा अंडरटेकिंग देने के बाद उन्हें कुछ समय की मोहलत देकर फायर सेफ्टी उपकरण जुटाने के लिए निर्देश दिए गए थे। अब जबकि लोकसभा चुनाव की वोटिंग हो चुकी है और सरकारी अधिकारी कर्मचारी चुनाव ड्यूटी से निवृत्त हो चुके हैं, फायर सेफ्टी को लेकर ऊंची बिल्डिंगों में एक बार फिर अभियान शुरू किया जाने वाला है।

शहर में 20 हजार से भी अधिक हाईराइज बिल्डिंगें-बताया जाता है कि शहर में 20 हजार से भी अधिक एक बिल्डिंग हैं, जो 12 मीटर से ऊंची है। निर्माण अनुसार इनमें अग्नि सुरक्षा उपकरण अर्थात फायर सेफ्टी इंतजाम होना जरूरी है। हालांकि इसके बाद भी सैकड़ों ऐसी बिल्डिंग हैं जिनमें फायर सेफ्टी के उपकरण नहीं है। इसलिए कुछ समय पूर्व प्रशासन ने एक जाहिर सूचना प्रकाशित कर ऊंची बिल्डिंगों में सहायक सेफ्टी इक्विपमेंट लगाने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद निरीक्षण में कुछ बिल्डिंगों को नोटिस भी दिए गए थे उसके बाद भी जिन्होंने सरकारी निर्देशों की अवहेलना की उन बिल्डिंगों को सील भी किया गया था।

एक सप्ताह का और समय उसके बाद फिर होगी कार्रवाई-कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि ऊंची बिल्डिंगों में फायर सेफ्टी इक्विपमेंट और नाम्स पूरे करने के लिए एक सप्ताह का समय और दिया गया है। इसके बाद फिर प्रशासन की टीम ऊंची बिल्डिंगें जिनमें फायर सेफ्टी नॉर्म्स नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगी। बिल्डिंग को सील भी किया जा सकता है।

बगैर अनुमति पेड़ काटा तो 10 हजार का स्पाट फाइन

पर्यावरण सुरक्षा के लिए उद्यान विभाग के अपर आयुक्त ने जारी किया आदेश

इंदौर। शहर में पर्यावरण सुधार और पेड़ों को बचाने के लिए नगर निगम अलर्ट मोड पर है। नगर निगम के अपर आयुक्त ने एक आदेश जारी किया है जिसमें बिना अनुमति पेड़ काटने पर 10 हजार रुपए का स्पाट फाइन करने का उल्लेख है। यह भी सामने आया है कि यह आदेश को एक नियम के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा। इस आदेश के बाद बिना अनुमति अवैध रूप से पेड़ों की कटाई करने वाले में भाई का माहौल पैदा होगा। साथ ही शहर में पेड़ों की कटाई पर भी रोक लगा सकेगी। पेड़ों की संख्या अधिक होने से शहर में बेहतर पर्यावरण भी रह सकेगा। वैसे भी निगम लगातार पौधारोपण को लेकर सटक रहा है। बारिश में और समय-समय पर पौधारोपण किया जाता रहा है।

उद्यान विभाग के अपर आयुक्त दिव्यांक सिंह ने पेड़ों की कटाई रोकने के लिए नियम बनाया है। इस नियम के तहत अवैध रूप से पेड़ काटने पर नगर निगम के उद्यान विभाग की टीम मौके पर ही पेड़ काटने वाले के खिलाफ 10000 का स्पाट फाइन लगाएगी। अपर आयुक्त सिंह उद्यान विभाग के सभी कर्मचारियों अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शहर में पेड़ों की संख्या पर लगातार नजर रखी जाए। कहीं भी पेड़ कटाई होते देखने पर तुरंत जांच की जाए कि पेड़ परमिशन लेकर काटा जा रहा है या बिना अनुमति के ही पेड़ की कटाई की जा रही है। बिना अनुमति पेड़ की कटाई होने पर निगम अमला तुरंत पेड़ काटने वाले के खिलाफ स्पाट फाइन की कार्रवाई करें। सिर्फ इस्पात फाइन की कार्रवाई ही नहीं करें अन्य वैधानिक कार्रवाई भी शुरू की जाए।

पौधारोपण भी बड़े पैमाने पर करने पर जोर

अपर आयुक्त सिंह अधिकारियों कर्मचारियों को यह भी निर्देश जारी किए हैं कि समय-समय पर और बारिश के पूर्व बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जाए जिससे शहर में बिगड़ते पर्यावरण को भी संतुलित किया जा सके। निगम के अन्य विभागों के कर्मचारी भी अपने-अपने झोन क्षेत्र में यह भी नजर रखें की कहानी बिना अनुमति पेड़ नहीं काटा जाए। पेड़ों को बचाने के पीछे उद्देश्य यह है कि शहर का पर्यावरण संतुलित बना रहे। साथ ही लोगों को भी बेहतर वातावरण मिल सके।

भू माफिया और बिल्डरों में मची हलचल

नगर निगम के इस आदेश के बाद शहर के बड़े भूमाफिया और बिल्डरों में हलचल मच गई है। इसका कारण यह है कि आम व्यक्ति तो अवैध रूप से पेड़ की कटाई नहीं करते हैं लेकिन निजी फायदा लेने के लिए बिल्डर और भू माफियाओं द्वारा ही निजी और सरकारी जमीन से पेड़ों की कटाई कर दी जाती है। साथ ही इस जमीन पर मकान और बिल्डिंग के बना दी जाती है। बड़ी संख्या में पेड़ काटने के कारण शहर का पर्यावरण भी बिगड़ जाता है।

उद्यान विभाग कर्मचारी की भी बढ़ सकती है अन्य आय

यह आदेश जहां एक और पेड़ों की कटाई रोकेगा वही उद्यान विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की भी अन्य आय को बढ़ावा देगा। इसका कारण यह है कि जब उद्यान विभाग की टीम या कर्मचारी पेड़ की अवैध रूप से कटाई होता देख मौके पर पहुंचेगा तो वह सीधे 10 हजार का जुर्माना लगाने का हवाला देते हुए मोटी रकम रिश्वत में प्राप्त कर सकता है।

प्राचीन मंशापूर्ण शनि मंदिर पर तीन दिवसीय शनि जयंती महोत्सव 4 जून से

इन्दौर। यंग इंडिया क्लब के तत्वावधान में जिंसी चौराहा स्थित प्राचीन मंशापूर्ण शनि मंदिर पर तीन दिवसीय शनि जयंती महोत्सव का दिव्य अनुष्ठान 4 से 6 जून तक आयोजित होगा । इस दौरान शनि भक्तों को शनि पीड़ा निवारण पुस्तिका निःशुल्क भेंट की जाएगी। क्लब के अध्यक्ष श्याम अग्रवाल, डॉ. निर्मल महाजन एवं सतीश सेन ने बताया कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी महोत्सव की जोरदार तैयारियां शुरू हो चुकी है। महोत्सव में इस बार हंस पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी रामचरणदास, खातीपुरा एवं पंचकुइयां राम मंदिर के महामंडलेश्वर स्वामी रामगोपाल दास, पीपलखूंटा आश्रम के दाड़कीवाले बाबा महंत दयारामदास महाराज, महामंडलेश्वर राधे राधे बाबा, अखंडधाम के महामंडलेश्वर डॉ. स्वामी चेतन स्वरूप, फलाहारी आश्रम अरण्य धाम के महंत श्रीराम महाराज, कबीर पंथी मंदिर जिंसी के महंत नानक साहिब, वीर बगीची पीठाधीश्वर महंत पवनानंद महाराज, धरावरा धाम के महंत शुकदेव दास महाराज, वीरेश्वर हनुमान मंदिर के महंत देवकीनंदन दास, राजेंद्र नगर हनुमान मंदिर के महंत लक्ष्मण दास महाराज एवं हंसदास मठ के पं. पवन दास महाराज जैसे संतो-महंतो के सानिध्य एवं राष्ट्रकवि पं.सत्यनारायण सत्तन, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, श्रीमती अर्चना जायसवाल, शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा, स्टेट प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल, नवनीत शुक्ला, नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे, पार्षद राजू भदौरिया, पार्षद भावना मनोज मिश्रा सहित अनेक विशिष्ट अतिथियों की मौजूदगी में शनि जयंती 6 जून को सायं 7.30 बजे जिंसी चौराहे पर महाआरती होगी। इसके पूर्व 4 जून को 7.30 बजे फूल बंगला श्रृंगारित होगा, 5 जून को सांय 7.30 बजे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय कर्मचारी रामायण मंडल द्वारा सुंदरकांड का पाठ तथा 6 जून , अमावस्या को सुबह 8 बजे से पूजा-अर्चना, दोपहर 12 बजे श्रृंगार एवं वट पूजा तथा दोपहर 4 बजे से यज्ञ हवन, सांय 6.30 बजे छप्पन भोग दर्शन एवं सांय 7.30 बजे महाआरती के बाद रात 8 बजे से महाप्रसादी वितरण के कार्यक्रम होंगे। समापन दिवस पर सभी भक्तों को शनि पीड़ा निवारण पुस्तिका का निशुल्क वितरण किया जाएगा।

बेटियों के सामने पति ने पत्नी की टामी कर दी हत्या

इंदौर। शराब के नशे में गैरेज संचालक ने बेटियों के सामने पत्नी की टामी से कई वार कर हत्या कर दी। दो बेटी पिता से अपनी मां की जान की गुहार लगाती रही, लेकिन नशे में चुर पिता ने उन्हें भी धक्का देकर दूर कर दिया। चंदन नगर थाना क्षेत्र के जवाहर टेकरी में रहने वाले भारत पटेल ने रविवार रात में पत्नी लक्ष्मी की विवाद के बाद हत्या कर दी। हत्या के बाद पुरे घर की धुलाई की और फिर वहीं बैठ गया। ससुराल में साले को फोन लगाकर कहां कि तुम्हारी बहन मर गई है। जब साला अंकित घर पहुंचा तो लक्ष्मी बेहोश पड़ी हुई थी। उसे अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित किया। स्वजन ने बताया कि आरोपित भारत रात करीब एक बजे नशे की हालत में घर पर पहुंचा और पत्नी से विवाद करने लगा।

आए दिन वह विवाद करता था। 25 वर्ष पहले इनकी शादी हुई थी। इनकी तीन बेटियां है। बड़ी की शादी हो चुकी है। वहीं 10 वर्षीय और 11 वर्षीय बेटी इनके साथ रहती है। आरोपित घर के बाहर की गैरेज चलाता है।

प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी जयश्री जैन द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स 13, प्रेस कॉम्प्लेक्स ए.बी. रोड इंदौर से मुद्रित एवं 22, प्रेस काम्पलेक्स, प्रेस हाऊस, ए.बी. रोड इंदौर 452008 से प्रकाशित। प्रधान संपादक- डॉ. राजेश जैन, मो. 9425322301 (डाक पंजीयन MP/IDC/1462/2016-2019)